

ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारत में व्यापारिक उद्देश्य तथा राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के कारण और परिणाम



Manu Yadav

Research Scholar Singhania University,
Pacheri Bari, Jhunjhunu, Rajasthan

भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के आने के समय, कम्पनी का उद्देश्य व्यापारिक था और इसने व्यापार में अत्यधिक धन कमाया। इसके साथ-साथ कम्पनी ने राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया तथा भारतीयों की आपसी फूट का लाभ उठाया। वास्तव में ईस्ट इंडिया कम्पनी ही भारत को गुलाम बनाने का साधन थी। राजा-नवाबों की आपसी कलह का लाभ उठाकर तथा भारतीयों में जातिगत भेद-भाव, धार्मिक भेद-भाव कबीले सम्बन्धी एवं जातीय भेद-भाव को भड़काकर, कूटनीतिक चालों से लूट-खसोट की, लड़ाईयों के द्वारा भारतीय प्रदेशों पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था। ब्रिटेन द्वारा भारत की लूट-खसोट ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी की शाखाओं को एकदम चौपट कर दिया था और उस विनाश, समृद्ध तथा प्राचीन देश के लोगों को जबर्दस्त गरीबी के गढ़ों में ढकेल दिया था। ब्रिटिश हस्तक्षेपकारियों ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों की उपेक्षा की थी और इस भाँति सिंचाई की व्यवस्था पर आधारित भारत की खेती का बंटाढार कर दिया था। देशी उद्योगों मुख्यतः करघे और चरखे का जो ब्रिटिश उस सूती कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकते थे जिनकी भारत के बाजारों में एक बाढ़ सी आ गई थी और करोड़ों भारतीयों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया था।³⁰

विलियम डिग्वी, सी० आई० एम० पी० ने लिखा है—“बीसवीं सदी के शुरू में करीब दस करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं, जिन्हें किसी समय भी पेट भर अन्न नहीं मिलता। इस अधःपतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी सम्य ओर उन्नति की दिशा में कहीं पर दिखायी नहीं दे सकती।”

Rajni Palm Dutt has written in his book “India Today” on page 103 “The ruin of Indian industry and commerce was followed by another disastrous result. It was not only the manufacturing towns and centres that were laid waste, and their population driven to crowd and over-crowd the villages, it was above all the basis of the old village economy, the union of agriculture and domestic industry, that received its mortal blow. The millions of ruined artisans and craftsmen, spinners, weavers, potters, tanners, smelters, smiths, alike from the towns and from the villages had no alternative save to crowd into agriculture. In this way India was forcibly transformed from being a country of combined agriculture and manufactures, into an agricultural colony of British manufacturing capitalism.”

22 जून 1757 प्लासी की विजय के बाद तथा 1764 ई० के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन की जड़े भारत से मजबूत होती चली गयी और उसने भारतीय जनता का आर्थिक शोषण आरम्भ किया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 1765 ई० में मिल जाने के फलस्वरूप लगान की व्यवस्था का भी उसी का अधिकार हो गया तथा उसने किसानों को मनमाने तरीके से लूटा जिससे किसानों की कमर यह जानकर दुःख होगा कि जबसे कम्पनी के पास दीवानी के अधिकार आए हैं, बंगाल के लोगों की द"ी पहले की अपेक्षा अधिक खराब हो गयी है।³¹

भारतीय जनता को दबाये रखने के लिए कम्पनी अब अपनी दे"ी फौजों का सहारा लेने लगी थी। इस फौज का मुख्य काम बदलकर फौजों के स्थान पर पुलिस का हो गया था। जीती गयी आबादी को दबाये रखना ही अब उसका मुख्य काम हो गया था। भारत की 20 करोड़ आबादी को अंग्रेज अफसरों की मातहती में काम करने वाली 2 लाख दे"ी फौज गुलाम बनाये हुए थी और स्वयं इस फौज को 40,000 अंग्रेज सैनिकों की शक्ति अपने नियंत्रण में किये रहती थी।³²

इतना ही नहीं भारत में अंग्रेजों ने खुले रूप से यह घोषणा की कि भारतीय एक हीन जाति है। वायसराय मेयो ने पंजाब के उपराज्यपाल को लिखा था—“अपने मातहतों को सिखाइये कि हम सभी संभ्रान्त अंग्रेज हैं जो एक हीन जाति पर शासन करने के एक शानदार काम में लगे हुए हैं।”³³ इससे स्पष्ट विदित होता है कि अंग्रेज भारतीयों को असभ्य, दीन-हीन तथा अज्ञानी समझते थे। उन्होंने न केवल हमारा आर्थिक दोहन ही किया बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी हमें अपमानित करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। हमारे साथ वे प"ुओं की भाँति व्यवहार करते थे।

रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक “आज का भारत” पृष्ठ 240 में उल्लेख किया है कि मालगुजारी—मालगुजारों और तहसीलदारों को अच्छी लग सकती है। लेकिन किसान के लिए तो यह प्रथा तबाही और बर्बादी का सामान तैयार कर देती है। उसे आमदनी के घटते-बढ़ते रहने पर भी एक ही रकम बराबर देनी पड़ती है। इसलिए बुरे दिनों में उसका दिवाला बोल जाता है और मजबूर होकर वह महाजन के जाल में फंस जाता है। बहुत खराब हालत होने पर, खींच-खाँच करके बाद मुद्धत के

कुछ छूटछाट हो भी गई, तो इससे कर्ज का सिलसिला बंद नहीं होता। कमीशन ने पूना जिले के कई गांवों से मालगुजारी वसूल करने के बारे में सामग्री इकट्ठा की थी। उस जांच से गांव वालों को मालगुजारी का भुगतान करने के लिए किस अभाव व ऋण का सामना करना पड़ता है का वर्णन निम्न टूट गयी और वह आर्थिक रूप से कंगाल हो गये। रिचर्ड बेचर ने लिखा है—“अंग्रेजों को

अंग्रेजों ने मालगुजारी के नाम पर अनेक भारतीय किसानों को दण्डात्मक कार्यवाहियों के रूप में भूमि से बेदखल कर दिया। जिससे ग्रामीणों की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई। राजस्व वसूलने वाले अधिकारियों के साथ शासन के प्रति वफादार कुछ व्यक्तियों को भूमि का स्वामी बना दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ व्यक्ति दलाल, बिचौलिये, राजा, नवाब, रियासतदारों के रूप में अंग्रेजी दरबार में गये और अंग्रेजी सरकारी खजाने में निश्चित धनराशि मालगुजारी के रूप में जमा करके और उसके बदले में जितना चाहे लगान वसूल करने की शर्तों के आधार पर अंग्रेजी शासकों से हाथ मिलाया हो।

1765 ई0 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपते समय तक मुगलों के दलाल बंगाल से कुल मिलाकर 8,18,000 पौंड मालगुजारी के रूप में वसूल करते थे। कम्पनी की एक ही साल की हुक्मत में 1765-66 में यह रकम बढ़कर 14,90,000 पौंड हो गयी और 1768 में 30,91,000 पौंड पहुँच गयी। किसानों को अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करने का यह रुझान जान-बूझकर कायम रखा गया। इस रुझान के मातहत बंगाल के किसानों से 1812-13 में 49,00,000 पौंड, 1822-23 में 1,46,00,000 पौंड और 1857-58 में 1,57,00,000 पौंड मालगुजारी वसूल की गयी। दूसरे शब्दों में कम्पनी अपनी कुल आय का लगभग एक तिहाई केवल भूमि से वसूल करती थी। रमेश चन्द्र दत्त के अनुसार बम्बई में महाराष्ट्र के किसानों से 1817 में 3,00,000 पौंड वसूल किया गया था। एक वर्ष बाद यह रकम बढ़ाकर 15,00,000 पौंड कर दी गयी थी।

स्थिति को पूरी तौर पर समझने के लिए कम्पनी के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए जमा की जाने वाली असीम सम्पत्ति पर भी निगाह डालनी चाहिए। स्वयं लार्ड क्लाइव भारत से इंग्लैण्ड जाते समय दो लाख पचास हजार पौंड की धनराशि अपने साथ ले गये थे। इसके अतिरिक्त वे भारत में 27,00 पौंड प्रतिवर्ष की आय देने वाली अपने नाम की एक जागीर भी छोड़ गये थे। 1759 और 66 के बीच बंगाल के अंग्रेज अधिकारियों ने रिवत के रूप में 25,00,000 पौंड और व्यक्तिगत क्षति के रूप में लगभग 40,00,000 पौंड वसूल किये थे। 1758 में एक वर्ष के अन्दर मीरजाफर को गद्दी पर बैठने का जो मूल्य चुकाना पड़ा था उसके आंकड़े देखकर तो सर चकराने लगता है। एक अंग्रेज इतिहासकार डब्ल्यू0 डब्ल्यू0 हंटर ने इस सम्बन्ध में नीचे लिखे आंकड़े दिये हैं—

यह समस्त धनराशि अंग्रेजों ने भारत में व्यय न करके इंग्लैण्ड में भेजी क्योंकि अंग्रेज तो भारत को लूटकर इंग्लैण्ड को मालामाल कर रहे थे। उनका उद्देश्य भारत का आर्थिक दोहन कर ब्रिटेन को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाना था।

Karl Marx has written in Newyork daily tribuen in 24 June 1853 “During the whole course of the 18th century, the Treasures transported from India of England were gained much less by comparatively insignificant commerce than by the direct exploitation of that country, and by the colossal fortunes there extorted and transmitted to England.

The total value of British exports during 1780 was 1,26,48,616 so that Indian trade amounted to only 1/32 of the entire foreign trade In 1850 the total exports to India from Great Britain and England were 80,24,000 so that it reached more than 1/8 of the whole export, and more than 1/4 of the foreign cotton trade. There exists now national debt of 500 million pounds, a continual decrease in the resources of the revenue and the corresponding increase in the expenditure dubiously balanced by the gambling income of the opium tax; now threatened with extinction by the Chinese beginning themselves to cultivate the poppy, and aggravated by the expenses to be anticipated from the senseless Burmese war.”

Karl Marx has written in 10 June 1853 in Newyour daily tribune “From 1818 to 1836 the export of twist from Great Britain to India rose in the proportion of 1 to 5,200. In 1834 the export of british Meslins to India hardly amounted to 60,00,000 yards, while in 1837 it surpassed 6,40,00,000. But at the same time population of Dacca decreased from 1,50,000 inhabitants to 20,000. This decline of Indian towns celebrated for their fabrics was by no means the worst consequence. British steam and science uprooted, over to whole surface of Hindustan, the union between agricultural and manufacturing industry.”

1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद से बंगाल की बाकायदा लूट आरम्भ हुई, 1760 में इंग्लैण्ड में झटके से फेंकी जाने वाली नारी (फ्लाईंग शटल) का ईजाद हुआ, उसी वर्ष धातु गलाने के काम में लकड़ी के स्थान पर पत्थर के कोयले का उपयोग आरम्भ हुआ, 1776 में क्राम्पटन ने कई तकुओं वाले चرخे की योजना बनायी, 1785 में पावर से चलने वाला कर्घा पेटेंट कराया गया और उसी वर्ष वेट ने भाप के इंजन में भी कई सुधार किये। इस प्रकार अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक औद्योगिक स्तर पर इंग्लैण्ड व्यापार की धारा को मोड़ने की स्थिति में आ गया था। उद्योग एवं निर्यात के विकास के साथ-साथ इंग्लैण्ड में औद्योगिक पूँजीपतियों का एक नया वर्ग पैदा हो गया था जो ब्रिटेन की व्यवसाय-नीति में परिवर्तन की माँग कर रहा था। भारत वर्ष के आर्थिक ढाँचे का निर्णायक ध्वंस इसी माँग का परिणाम था। जो भारत अभी तक मुख्यतया निर्यात करने वाला देश था वह अब अंग्रेजी माल का बाजार बनने जा रहा था। इस दिशा में पहला काम यह किया गया कि इंग्लैण्ड का बाजार

भारत के बने माल के लिये कानून द्वारा बन्द कर दिया गया। और चूँकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास भारतीय निर्यात व्यवसाय का एकाधिकार था जिसका प्रभाव दूसरे देशों के बाजारों पर भी पड़ना अनिवार्य था।

लार्ड मैकाले ने भारत की आर्थिक लूट व दमन का वर्णन करते हुए लिखा है—“कम्पनी के नौकर प्रायः अन्दरूनी (देश के अन्दर) व्यापार का एकाधिकार कम्पनी के लिए नहीं वरन् अपने लिये प्राप्त कर लेते थे। वे कम्पनियों को सस्ता बेचने और महंगा खरीदने पर मजबूर करते थे। वे अपने साथ अपने पर निर्भर रहने वाले कुछ ऐसे लोग रखते थे, जो प्रांतों में घूम-घूमकर गाँवों को उजाड़ने और आतंक या भय का राज्य कायम करते रहते थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रत्येक नौकर को अपने अफसर के सब अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक अफसर के हाथ में कम्पनी के सब अधिकार केन्द्रित थे। इस तरह बहुत थोड़े समय में सारे देश का धन कलकत्ते में खिंच आया और करोड़ों भारतवासी गरीबी और तबाही की चरम सीमा पर पहुँच गये। वे पहले भी मुगल शासन में निरंकुशता के नीचे रह चुके थे, लेकिन यह निरंकुशता उनके लिये एक नया अनुभव थी।”³⁶

इसके बाद तरह-तरह के नियमों और अन्तर्देशीय चुंगियों द्वारा भारतीय माल का उत्पादन रोकने या कम करने का प्रयास आरम्भ हुआ। फलस्वरूप देश के अन्दर का माल एक जगह से दूसरी जगह जाना रुक गया। उधर अंग्रेजी माल को खुली छूट थी। परिणामस्वरूप भारतीय वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया। इसने जुलाहों और कालियों के एक विशाल समुदाय को बेरोजगार बना दिया। बंगाल और बिहार में यह प्रक्रिया तेजी के साथ फैली। दूसरे-दूसरे स्थानों पर भी ब्रिटिश शासन और रेलवे के विस्तार के साथ-साथ उसका प्रभाव धीरे-धीरे पड़ा। उन्नीसवीं शताब्दी भर यह प्रक्रिया चलती रही। धीरे-धीरे पोत निर्माण उद्योग, धातु का काम, कागज तथा अन्य पुराने उद्योग भी समाप्त हो गये।³⁷

कार्ल मार्क्स ने लिखा है—“1818 से लेकर 1836 ई० तक ग्रेट ब्रिटेन से भारत में बटे रेमी धागे का निर्यात 1 और 5200 के अनुपात में बढ़ गया। 1824 ई० में ब्रिटिश मलमल का भारत को निर्यात मुक्तिकाल से 60,00,000 गज था जबकि 1837 में यह 6,40,00,000 गज से भी अधिक बढ़ गया। इसी समय ढाका की आबादी 1,50,000 से घटकर 20,000 रह गयी। सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध भारतीय नगरों का पतन ही केवल ब्रिटिश नीति का सबसे बुरा परिणाम नहीं था। अंग्रेजी मिलों तथा विज्ञान ने सारे भारत में कृषि तथा उद्योगों के बीच सम्बन्ध को जड़ से उखाड़ दिया।”³⁸

इंग्लैण्ड के रूई उद्योग का भारत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। 1834-35 में गवर्नर-जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा—“इस प्रकार की विपत्ति का शायद ही भारतीय व्यापार के इतिहास में कोई समानांतर मिलता हो। भारत के रूई बुनने वालों की हड्डियाँ भारत के मैदानों में सड़ रही हैं।”

संक्षेप में, जुलाहों को हर तरह से तंग किया गया। बेचारे जुलाहे विवश होकर अपना पैतृक धन्धा गये और खेतों में जाकर मजदूर बन गये। इस तरह से सूरत, ढाका तथा मुर्शिदाबाद जैसे विशिष्ट-प्रसिद्ध बढ़िया सूती कपड़ा बनाने के केन्द्र नष्ट हो गये।³⁹

अंग्रेज इतिहासकार ग्रिफिट ने उल्लेख किया है कि स्वतन्त्र व्यापार की नीति तथा ब्रिटिश मशीनों के द्वारा बनाये हुए माल के मुकाबले में भारतीय माल को संरक्षण न देने के कारण भारतीय कारीगर और उद्योगपति नष्ट हो गये।⁴⁰

रजनी पाम दत्त ने लिखा है—“न केवल वस्तुएं बनाने वाले नगर तथा केन्द्र अंग्रेजों द्वारा बर्बाद किए गये और उनकी आबादी को ग्रामों में भीड़ करने के लिए भेज दिया गया, अपितु ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुराने आधार को नष्ट कर दिया गया, अर्थात् कृषि और घरेलू उद्योगों के मेल को ही घातक धक्का लगा। लाखों कारीगर, शिल्पी, सूत कातने वाले, जुलाहे, कुम्हार, चमड़ा रंगने वाले, धातु पिघलाने वाले, लुहार इत्यादि के पास गांवों में भीड़ करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहा। इस तरह से भारत कृषि तथा उद्योगों के मेल को जबर्दस्ती तोड़कर भारत को ब्रिटिश औद्योगिक पूँजीवाद का उपनिवेश बना दिया गया।”

अंग्रेज इतिहासकार सर विलियम हन्ट ने स्वीकार किया है—“ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारतीय किसानों की दशा सबसे दयनीय थी। एक ओर भारतीय किसानों के लिए परिवार के लोग भूस्वामियों द्वारा निचोड़े जा रहे थे तथा दूसरी ओर सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती कर वेतन और पेन्शन—राशि में कमी की जा रही थी। इसके विपरीत गोरे सैनिकों की सुविधाएं बढ़ा दी गई थी, जो रंग-भेद और जाति-भेद के नाम में चूर होकर भारतीय सैनिकों के साथ भ्रष्ट व्यवहार करने लगे थे।”⁴¹

उन्नीसवीं शताब्दी में 28 अकाल पड़े, जिनमें से 18 अकाल उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम 25 वर्षों में पड़े। जिसमें लगभग 285 लाख लोग मरे। भारत की औपनिवेशिक लूट-खसोट ने जो ब्रिटिश-शासकों की सम्पन्नता का एक स्रोत थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को खोलला कर दिया जिसमें भारतीयों में गरीबी बढ़ी। सिचाई के अभाव में कृषि विनाश की ओर चली गयी। कुटीर और लघु दोनों प्रकार के उद्योग-धन्धों की नींव हिल गयी। भारतीयों के भूखें मरने नौबत आ गयी। भारत में जमींदारों और बंधुआ मजदूर-व्यवस्था भी नाममात्र की रह गयी थी। देश का विकास रुक गया तथा भारतीयों को रोटी मिलना भी दूभर हो गया था। दूसरी ओर अंग्रेजों के करों का भार इतना बढ़ गया कि जनता डूबती चली जा रही थी।